powder attracts 30% and 35% excise duty respectively.

(f) Laundry soaps are generally cheaper and more widely used as compared to detergent cakes and powder and hence a lower duty of 5% is justified.

Forward and Real Trading in Stock Exchanges

85. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI G.G. SWELL:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what were the last year's total transactions in forward and real trading in stocks, shares, bonds, etc.;

(b) what is the amount collected on stamp duty;

(c) at which stage of the transactions of stocks duty is charged and at what rate;

(d) what are the advantages and disadvantages of forward trading in stock exchanges;

(e) whether forward trading is permitted in developed and developing countries;

(f) whether forward trade is criticised as speculation, if so, what are the facts; and

(g) whether FIIs are facing the problem of custodial services; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (g) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आयात प्रतिस्थापन

84. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी ऋण पर निर्भरता को कम करने हेतु कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन उठाए गए कदमों की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(ग) कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के उपायों से विदेशी ऋण पर निर्भरता में कितने प्रतिशत कमी हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वाधिक प्रभावशाली नीति उपाय एक सुदृढ़ विनिमय दर नीति का पालन करना है। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा पालन की गई विनिमय दर नीति में, आयात नियंत्रणों की बड़ी संख्या के निरसन और आयात शुल्कों में कमी के बावजूद आयात वृद्धि में एक स्थिरता दिखाई दी है। नीति ने प्रभावशाली रूप से आयात प्रतिस्थापनों को प्रोत्साहित किया है तथा आयातों में भार वृद्धि के डर को दूर कर दिया है।

(ख) हालांकि 1992-93 में आयातों में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उनमें 1993-94 के पहले नौ महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट आंशिक रूप से तेल की कीमतों के कम होने के कारण है लेकिन अधिकाशतः विनिमय दर नीति के आयात-प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। पैट्रोल तेल स्नेहक (पी०ओ०एल०)-भिन्न आयातों में 1993-94 के पहले नौ महीनों के दौरान 2.2 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि दिखाई दी है। देश के व्यापार घाटे में भी तेजी से गिरावट आई है। 1992-93 के पहले नौ महीनों में 3.6 बिलियन डालर की तुलना में, पहले नौ महीनों में यह केवल 732 मिलियन डालर थी। व्यापार और चालू खाते में सुधार के परिणामस्वरूप विदेशी ऋण की वृद्धि में भी तेजी से गिरावट आई है।

(ग) 1990-91 में भारत के विदेशी ऋण में 8.1 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। यह 1991-92 में गिरकर 1.4 बिलियन डालर और 1992-93 में 4.8 बिलियन हो गया तथा 1993-94 के पहली छमाही में यह केवल

296 मिलियन डालर रह गया है। यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई विनिमय दर तथा अन्य बृहत् आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप विदेशी ऋण की वृद्धि में गिरावट आई है।

स्वैच्छिक एजेंसियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

87. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता-राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह राशि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिये असमान रूप से दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1993 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत एवं संवितरित विवरण राज्य-वार सहायता में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) स्वैच्छिक एजेंसियों को निधियों की मंजूरी और निर्गम विभिन्न राज्यों से उनसे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर आधारित होता है। यह सहायता के लिए मात्र औद्योगिक रोजगार उन्मुख गतिविधियों में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों पर भी निर्भर करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र के कम विकसित राज्यों सहित अधिकांश राज्यों की स्वैच्छिक एजेंसियों को प्राप्त हुई है।

विवरण

(लाख रुपये)

1.4.1988 से 31.3.1988 तक राज्य-वार स्वीकृतियां एवं संवितरण

क्रम० सं०	राज्य	स्वीकृतियां	संवितरण
1.	बिहार	4.00	40.10
2.	उड़ीसा	46.77	43.13
3.	पश्चिम बंगाल	35.58	27.63
4.	असम	10.90	9.79
5.	मणिपुर	3.15	5.76
6.	मेघालय	1.60	1.25
7.	नागालैंड	5.53	15.67
8.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	8.55
9.	मिजोरम	7.00	5.50
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (सामान्य कार्यक्रम)	401.55	400.65
11.	हरियाणा	3.00	2.14
12.	राजस्थान	22.50	17.40
13.	उत्तर प्रदेश	5.95	4.95
14.	दिल्ली	31.90	26.60
15.	गुजरात	37.77	30.99
16.	मध्य प्रदेश	15.75	4.00